

भाग—III**हरियाणा सरकार**

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अप्रैल, 2026

संख्या का०आ० 14/के०अ० 67/1957/धा० 30ख/2026.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) की धारा 30ख की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1क) के उपबन्धों की उल्लंघना के लिए अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन हेतु हरियाणा राज्य में अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में गठित करते हैं;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 30ख की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उक्त न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT****Notification**

The 10th April, 2026

No. S.O.14/C.A 67/1957/S. 30B/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the Governor of Haryana for the purposes of providing speedy trial of offences for contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (1A) of section 4 hereby constitute the Courts of District and Sessions Judges and all the Additional District and Sessions Judges as Special Courts in their respective district in the State of Haryana;

Further, in exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 30B of the said Act and with the concurrence of the Punjab and Haryana High Court, the Governor of Haryana hereby appoints the District and Sessions Judges and all the Additional District and Sessions Judges as Judges of the said Courts.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.